(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

फसल बीमा योजना का सभी राज्यों में लागू किया जाना

2814. **श्री राधा किशन मालवीय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार फसल बीमा योजना को अनिवार्य रूप से लागू करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बैंकों से फसल ऋण न लेने वाले किसानों के लिए भी फसलों का बीमा किया जाएगा ; और

(ग) क्या भारत सरकार इस योजना को इस प्रकार कार्यान्वित करने के प्रश्न पर विचार करेगी कि प्रत्येक किसान जिसकी फसल का बीमा किया जाए उसको वास्तव में होने वाली हानि के अनुरूप ही क्षतिपूर्ति की जाए ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं । अभी नहीं ।

(ग) यह योजना क्षेत्र आधारित है और यदि औसत-उपज में कोई कमी हो जाए तो इस क्षेत्र के सभी बीमाकृत किसान क्षतिपूर्ति दावों के हकदार होते हैं, परन्तु वैयक्तिक किसानों को उनके द्वारा उठाई गई वास्तविक हानि के आधार पर क्षतिपूर्ति नहीं की जाती ।

Madras project approved by the UNDP

2815. SHRI R. SAMBASIVA RAO: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the United Nations Development Programme has recently approved a project for the development and management of water resources in Madras; and

(b) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI B. SHANKARANAND): (a) and (b) The United Nations Development Programme (UNDP) has approved a Project for Development and Management of Water Resources in Madras with a view to augment the drinking water supply to Madras City. The implementing agency for this Project is Madras Water Supply and Sewerage Board. The duration of the Project is 30 months starting from November, 1986. The Government of India input is Rs. 6.7 million (in kind) and the UNDP input as indicated in the Project Document is US $ 619650 which will be in the form of consultancy, fellowships, equipment and miscellanious items.

दिल्ली नगर निगम अधिनियम का उल्लंघन

2816. **कुमारी सुशीला तिरिया** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ प्रापर्टी डीलर प्रेम नगर और नांगलोई, नजफगढ, जफरपुर कलां क्षेत्र के निकट डिलाइट विहार में पिछले तीन वर्षों से दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 का उल्लंघन कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन प्रापर्टी डीलरों के विरुद्ध कोई भी जांच या केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जांच कराने का या कोई कार्यवाही करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (समय-समय पर संशोधित) का उल्लंघन करने के लिये कथित प्रापर्टी डीलरों का कोई रिकार्ड दिल्ली नगर निगम के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि, दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के उपबंधों के उल्लंघन के लिये 1985-86 के दौरान उनके द्वारा कई मामलों में अभियोजन आरम्भ किये गये है। नांगलोई, नजफगढ, जफरपुर कला क्षेत्र के अभियोजन के लिये कुछ और मामले उनके द्वारा तैयार किये जा रहे हैं।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच के लिये कोई प्रस्ताव नहीं है।

Fire safety equipment in multi-storeyed buildings

2817. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that most of the Multi-storeyed buildings in the country and particularly in the capital do not have proper fire safety equipments;

(b) if so, whether Government propose to take strict action against the owners of the multi-storeyed buildings who do not take all precautions for fire safety measures in these buildings; and

(c) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) Cases of inadequacy of fire safety equipment in the capital have come to the notice of the Government. Though hard information is not available for the entire country but the position is reported to be by and large, the same.

(b) and (c) Parliament has recently passed the Delhi Fire Prevention and Safety Act, 1987, which seeks to deal with the problem comprehensively and effectively. Rules framed thereunder are being notified.

Payment of overtime allowance and medical reimbursement by FCI and Central Warehousing Corporation

2818. SHRI VIRENDRA VERMA: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) the amount of annual overtime allowance, category-wise, paid to the employees of the Food Corporation of India and the Central Warehousing Corporation during the last three years, year-wise and also during the current year till date;

(b) the annual amounts reimbursed on account of medical charges to the employees, category-wise to the employees of the above mentioned organisations during the above period; and

(c) what precise measures have been taken by Government to bring down the overtime allowance and medical reimbursement to the minimum?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) and (b) The amount paid by the Food Corporation of India and the Central Warehousing Corporation to their employees during the last three years on account of overtime allowance and